Atmosphere in Delhi University

940. SHRI SHANKER DAYAL SINGH.
SHRI R. S. PANDEY:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether atmosphere in Delhi University has been polluted as a result of dissensions and discord among the teachers of the University and non-cooperation of Student Union; and

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government to resolve the matters involved.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI S. NURUL HASAN): (a) and (b). The University of Delhi has been functioning normally since it reopened on January 2, 1973. A Committee consisting of 12 teachers and 12 students has been appointed to look into the various problems. Both the teachers and the students of the University are fully co-operating in the matter.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में संचालन समिति का गठन

941. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्री एच० एम० पटेल :

क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की संचालन समिति का गठन अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा किन अर्थों में भिन्न है;

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में गत वर्ष कितने दिनों की अधिकृत छुट्टी रही, कितने दिन पढ़ाई हुई और उपद्रवों के कारण विश्वविद्यालय कितने दिन बन्द रहा; और

(ग) इस समय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शान्ति एवं व्यवस्था की क्या स्थिति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) बनारस हिन्दू विश्वविधालय अधिनियम 1915 के अनुसार विश्वविद्यालय की एक कार्यकरी परिषद है जिस पर विश्वविद्यालय के राजस्व तथा सम्पत्ति के सप्रबन्ध एवं संचालन और उसके प्रशासनिक मामलों का उत्तरदायित्व है। विश्वविद्यालय के मौजूदा संविधियों अनुसार कार्यकारी परिषद में एक कुलपति तथा कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत आठ व्यक्तियों की व्यवस्था है। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विश्वविद्यालयों की कार्यकारी परिषद का संविधान अलग-अलग होता है। सामान्यत: परिषद में कुलपति समकुलपति यदि कोई हो, कुछ डीन तथा अध्यापक और कोर्ट द्वारा मनोनीत व्यक्ति एवं कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति शामिल होते हैं। जब बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित किया जाएगा तब कार्यकारी परिषद में और अधिक अध्यापक, कोई द्वारा मनोनीत व्यक्तियों एवं कुलाध्यक्ष को शामिल किया जाएगा।

(ख) 1971–72 के शैक्षणिक सत्र के दौरान विश्वविद्यालय में ग्रीष्म कालीन अवकाश के अतिरिक्त 56 प्राधिकृत छुट्टियां थीं। शिक्षा संकाय को छोड़ कर विभिन्न संकायों में कक्षाएं 13 सितम्बर, 1971 को छात्र उपद्रव की वजह से निलंबित की गई थीं। 15 अक्टूबर 1971 से कक्षाएं क्रमिक रूप में शरू हुई।

(ग) हिंसा, आगजनी, लूट, अध्यापक तथा विद्यार्थियों पर आक्रमण एवं विध्वंसक कार्यों की वजह से विश्वविद्यालय 8 दिसम्बर, 1972 को बन्द करना पड़ा था। 8 फरवरी, 1973 से संकायों ने क्रमिक रूप से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है और यह आशा की जाती है कि सभी संकाय अपना कार्य 28 फरवरी, 1973 से करना शुरु कर देंगे।

चीनी के कारखाने तथा उनकी उत्पादन क्षमता

942. श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चीनी के कितने कारखाने हैं और राज्य-वार उन की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों में देश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) सरकारी, सहकारी तथा निजी चीनी कारखानों की इस समय अलग अलग संख्या और उत्पादन क्षमता क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश में इस समय स्थापित चीनी मिलों की संख्या 234 है। चीनी मिलों की राज्यवार संख्या और उनकी स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता जोकि 40.12 लाख मी० टन है, को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी–4275/73)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का कुल उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

मौसम (अक्तूबर से सितम्बर तक)	चीनी का उत्पादन (लाख मी० टन)
1969–70	42.62
1970–71	37.40
1971–72	31.13

(ग) देश में सरकारी, सहकारी और निजी क्षेत्रों में चीनी मिलों की राज्यवार संख्या और उनकी स्थापित वार्षिक उत्पादन क्षमता बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या LT–4275/73)

बिहार सरकार द्वारा चीनी–व्यापार को अपने हाथ में लेना

943. श्री शंकर दयाल सिंह :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सरकार ने चीनी वितरण का पूर्ण व्यापार अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) क्या चीनी समस्या के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच बातचीत हुई थी और क्या केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है ?